10 महीने बाद भी जिंदा है सवाल: उटंगन नदी में 12 युवकों की मौत का जिम्मेदार कौन?

राम कृपाल सिंह

आगरा। करीब दस माह बीत चुके हैं, लेकिन आगरा जनपद की खेरागढ़ तहसील में हुई वह दर्दनाक घटना आज भी लोगों के जेहन से पूरी तरह नहीं मिट पाई है। 20 अक्टूबर 2025 को देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान उटंगन नदी में बने एक गहरे गड्ढे में डूबने से एक ही गांव के 12 युवकों की मौत हो गई थी। यह हादसा न केवल 12 परिवारों की दुनिया उजाड़ गया, बल्कि कई ऐसे सवाल भी छोड़ गया जिनका जवाब आज तक नहीं मिल सका।

समय बीतने के साथ घटनाएं अक्सर खबरों से गायब हो जाती हैं, लेकिन जिन परिवारों ने अपने बेटे खोए, उनके लिए हर दिन उसी त्रासदी की याद लेकर आता है। सबसे बड़ा सवाल आज भी कायम है–आखिर इन 12 युवकों की मौत का जिम्मेदार कौन है?

हादसे के बाद वादों की बौछार, लेकिन जमीन पर सन्नाटा

दुर्घटना के बाद प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि पीड़ित गांव पहुंचे। संवेदनाएं व्यक्त की गई, आर्थिक सहायता, सड़क, विद्यालय और अन्य विकास कार्यों की घोषणाएं की गई। उस समय ऐसा लगा कि पीड़ित परिवारों को न्याय और सहयोग दोनों मिलेगा।

लेकिन करीब दस महीने बाद जब इन घोषणाओं की पड़ताल की गई तो तस्वीर अलग दिखाई दी।

इस संवाददाता ने मृतकों के परिजनों से संपर्क किया। सबसे पहले बातचीत यादव सिंह से हुई, जिनके दो बेटे इसी हादसे में काल के गाल में समा गए थे। उन्होंने बताया कि घटना के बाद उन्होंने किसी से कोई मांग नहीं की, लेकिन जो सार्वजनिक घोषणाएं की गई थीं, उनमें से अधिकांश आज तक पूरी नहीं हुई।

परिजनों का कहना है कि नेताओं ने घटनास्थल पर आकर आश्वासन तो दिए, लेकिन बाद में किसी ने उनकी सुध नहीं ली। उनका आरोप है कि अधिकांश वादे केवल उस समय की संवेदनात्मक और राजनीतिक प्रतिक्रिया तक सीमित रह गए।

आखिर कैसे हुआ था हादसा?

20 अक्टूबर 2025 को नवदुर्गा महोत्सव के समापन पर गांव के युवकों ने देवी प्रतिमा का विसर्जन खेरागढ़ से गुजरने वाली उटंगन नदी में करने का निर्णय लिया था।

मृतक के पिता यादव सिंह के अनुसार, यह पूरा आयोजन गांव के युवाओं द्वारा किया जा रहा था। नदी में सामान्य दिनों में पानी कम रहता था, इसलिए किसी को किसी बड़े खतरे की आशंका नहीं थी।

जब युवक प्रतिमा लेकर नदी पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। शासन के निर्देशों के अनुसार प्रतिमाओं का विसर्जन नदी में न कराकर नगर पंचायत द्वारा बनाए गए विसर्जन कुंड में कराया जाना था। पुलिस ने युवकों को स्पष्ट रूप से नदी में जाने से मना किया।

प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के अनुसार, इसके बाद युवकों ने प्रतिमा वापस ले जाने का निर्णय लिया। हालांकि बाद में कुछ युवक दूसरे रास्ते से नदी तक पहुंच गए।

नदी के अधिकांश हिस्से में पानी घुटनों तक था, लेकिन जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां लगभग 10 फीट या उससे अधिक गहरा गड्ढा था। बताया जाता है कि युवकों को इस गहराई की जानकारी नहीं थी। प्रतिमा विसर्जन के दौरान पहला युवक गहरे पानी में चला गया और उसे बचाने के प्रयास में एक-एक कर कुल 12 युवक डूब गए।

सात दिन चला रेस्क्यू ऑपरेशन

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंचे। लेकिन बचाव अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हुआ।

गोताखोरों के अनुसार, पूरे नदी क्षेत्र में पानी कम था, लेकिन जहां हादसा हुआ वहां गहरी गाद और दलदल जैसी स्थिति थी। कई बार गोताखोर स्वयं भी खतरे में पड़ गए।

आखिरकार स्थानीय स्तर पर कंप्रेसर की मदद से नदी की तलहटी में जमी गाद हटाई गई और सात दिन तक चले अभियान के बाद एक-एक कर सभी 12 शव बरामद किए जा सके।

जांच हुई, लेकिन जवाब नहीं मिला

घटना के बाद प्रशासन ने जांच का भरोसा दिया था। परिजनों का कहना है कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि पूरी घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी।

जब वर्तमान थाना प्रभारी से इस संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास इस मामले से संबंधित कोई शिकायत या एफआईआर उपलब्ध नहीं है तथा अधिक जानकारी तत्कालीन थाना प्रभारी से प्राप्त की जा सकती है।

वहीं, एसडीएम खेरागढ़ के अनुसार घटना की उच्च स्तर पर जांच कराई गई थी। उनके मुताबिक सैटेलाइट सर्वे में यह पाया गया कि नदी में केवल उसी स्थान पर गहरा गड्ढा था, जबकि शेष नदी सामान्य थी।

हालांकि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब भी अनुत्तरित है–यदि पूरी नदी सामान्य थी तो केवल उसी स्थान पर इतना गहरा गड्ढा कैसे बना? क्या यह प्राकृतिक था या किसी अन्य कारण से बना? इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर अब तक सामने नहीं आया है।

12 अधूरे सपनों की कहानी

इस हादसे में जिन युवकों की जान गई उनमें ओमपाल, गगन, हरीश, अभिषेक, ओके, महावीर, कारण, भगवती, गजेंद्र, मनोज, दीपक और वीनेश शामिल थे। इनकी आयु लगभग 16 से 27 वर्ष के बीच थी। अधिकांश परिवार आर्थिक रूप से साधारण पृष्ठभूमि से जुड़े हैं।

परिजनों का कहना है कि उन्होंने अपने घरों के सहारे खो दिए। उनके अनुसार समय के साथ समाज और राजनीति आगे बढ़ गई, लेकिन उनके लिए जीवन आज भी उसी दिन पर ठहरा हुआ है।

न्याय और जवाब का इंतजार

यह घटना केवल एक हादसा नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और जवाबदेही से जुड़े कई गंभीर प्रश्न छोड़ गई। यदि विसर्जन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था थी, तो युवक दूसरे रास्ते से नदी तक कैसे पहुंच गए? यदि नदी में खतरनाक गड्ढा मौजूद था, तो क्या उसकी पहचान कर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे? और यदि घटना की जांच हुई, तो उसके निष्कर्ष सार्वजनिक क्यों नहीं हुए?

इन सवालों के जवाब आज भी पीड़ित परिवार तलाश रहे हैं।

जब तक इन प्रश्नों का स्पष्ट और पारदर्शी उत्तर नहीं मिलता, तब तक खेरागढ़ की उटंगन नदी में डूबे उन 12 युवकों की मौत केवल एक बीती हुई घटना नहीं, बल्कि व्यवस्था से जवाब मांगता एक जीवित सवाल बनी रहेगी।

दीवानी न्यायालय परिसर, आगरा में वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन

अग्र भारत संवाददाता

आगरा। शनिवार को को समय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा संजय कुमार मलिक तथा श्रीमती तृप्ता चौधरी, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, आगरा के कर-कमलों द्वारा दिवानी न्यायालय परिसर, आगरा में पर्यावरण संरक्षण एवं हरित वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान जनपद न्यायाधीश ने अधिक से अधिक वृक्ष लगाने तथा उनके संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि वृक्ष मानव जीवन एवं पर्यावरण के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने सभी न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों से वृक्षारोपण को जन-आंदोलन का स्वरूप देने तथा लगाए गए पौधों के नियमित संरक्षण का आह्वान किया।

इस अवसर पर अमरजीत, अपर जिला जज, शारिब अली, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा सहित जनपद न्यायालय, आगरा के समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सभी ने उत्साहपूर्वक वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

कार्यक्रम का समापन पर्यावरण संरक्षण की सामूहिक शपथ के साथ हुआ तथा सभी उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अधिकाधिक वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण का संकल्प लिया।

निर्माणाधीन 02 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का सीडीओ ने किया निरीक्षण

अग्र भारत सवाददाता

आगरा। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विकास खण्ड अकोला की ग्राम पंचायत जारूआ कटरा एवं विकास खण्ड सैंया की ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर में निर्माणाधीन 02 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया गया।

सर्व प्रथम मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अकोला की ग्राम पंचायत जारूआ कटरा में निर्माणाधीन कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के निर्माण में पाई गई आंशिक कमियों को कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को नोट कराते हुए तत्काल ठीक कराकर अवगत कराने निर्देश दिए गये। इस विद्यायल में बाउन्ड्रीवॉल का निर्माण आवास विकास परिषद द्वारा कराया जा रहा है। मौके पर परिसर के दाहिने ओर से बाउन्ड्रीवाल का निर्माण ग्रामीणों के अवरोध के कारण रुका हुआ था। इस सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी अकोला एवं क्षेत्रीय लेखपाल को संयुक्त रूप से मौके का मुआयना कर विद्यालय के नाम पंजीकृत भूमि के अनुसार सीमांकन कर बाउन्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गये।

इसी प्रकार विकास खण्ड सैया की ग्राम पंचायत में निर्माणाधीन उच्चीकृत कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय में निरीक्षण के समय विद्यालय में बने शौचालयों एवं स्नानघर के अन्तर्गत यूरीनल सीट, शौचालय सीट, वॉश बेसिन, शीशा एवं आवश्यक सामग्री स्थापित नहीं पाई गई। जिसे नियमानुसार एवं मानक अनुसार लगाने के निर्देश दिए गए ।

उक्त के अतिरिक्त दीवारों पर सीलन आ रही थी उसे भी तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए गए । इसके अतिरिक्त भवन की विद्युत वायरिंग एवं रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का कार्य अधूरा पाया गया।

इस सम्बन्ध में सैया में कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अवर अभियन्ता महेश चन्द को कारण बताओ नोटिस जारी करने एवं ठेकेदार के विरुद्ध समयान्तगर्त कार्य पूर्ण न करने के लिए पेनल्टी अधिरोपित करने के निर्देश अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को दिये गये।

अधिशासी अभियंता देते हैं कमीशन पर ध्यान

ग्रामीण अभियंता विभाग के अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार की बात करें तो उन पर कई जनपदों का चार्ज होने के कारण आगरा में होने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं अलावा इसके बताया जाता है कि कमीशन का खेल भी विभाग में निराला है अधिशासी अभियंता के साथ-साथ उनके अधीनस्थ भी ठेकेदारों से पहले कमिशन तय करते हैं उसके बाद निर्माण कार्य शुरू होता है।

अग्र भारत की खबर का असर

खबर प्रकाशित होने पर अधिकारियों की नींद टूटी, सर्विस रोड पर पर मरम्मत का कार्य शुरू, जल भराव से मिलेगी निजात

बारिश में जलभराव से पुलिस चौकी का रास्ता बना मुसीबत

गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर फरियादी और राहगीर

अग्र भारत संवाददाता

सिकंदरा। आगरा-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग रुनकता स्थित पुलिस चौकी के सामने बारिश के [illegible] होने वाला जलभराव लोगों के लिए मुसीबत बन [illegible] है। सर्विस रोड पर पानी भरने से पुलिस चौकी [illegible] पहुंचने का रास्ता जलमग्न हो जाता है। इसके च[illegible] फरियाद लेकर चौकी पहुंचने वाले लोगों के साथ राहगीरों को भी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है।

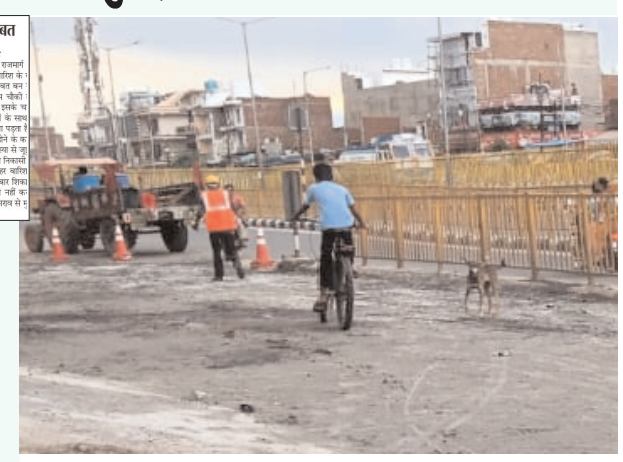

पुलिस चौकी के पीछे घनी आबादी होने के क[illegible] स्थानीय लोगों को भी जलभराव की समस्या से जू[illegible] पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जल निकासी [illegible] समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हर बारिश [illegible] सर्विस रोड पर पानी भर जाता है। कई बार शिका[illegible] के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं क[illegible] गया है। ग्रामीणों ने एनएचएआई अधिकारियों से जल्द जल निकासी की व्यवस्था कर सर्विस रोड को जलभराव से मु[illegible] कराने की मांग की है।

सर्विस रोड पर चलता मरम्मत कार्य

अग्र भारत सवाददाता

सिकंदरा । आगरा-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित रुनकता पुलिस चौकी के सामने सर्विस रोड पर जलभराव की समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद अग्र भारत की खबर का असर देखने को मिला हैं। संबंधित विभाग ने सड़क की मरम्मत का कार्य तो शुरू करा दिया, लेकिन समस्या की मुख्य वजह बने जर्जर और चोक पड़े नाले की ओर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है।स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बारिश में नाला चोक होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पाती और पूरा पानी सर्विस रोड पर भर जाता है। इसी वजह से पुलिस चौकी पहुंचने वाले फरियादियों, राहगीरों और आसपास के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।राहगीरों का कहना है कि केवल सड़क की मरम्मत से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। जब तक जर्जर नाले की मरम्मत और उसकी नियमित सफाई नहीं कराई जाएगी, तब तक हर बारिश में जलभराव की स्थिति बनी रहेगी। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क निर्माण के साथ-साथ नाले का भी तत्काल पुनर्निर्माण और सफाई कराई जाए। उनका कहना है कि जर्जर नाला कभी भी धंस सकता है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो लोगों की जान-माल का नुकसान होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।

03 से 10 अगस्त तक आगरा में चलेगा 'दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0', रोजगार व स्वरोजगार के मिलेंगे अवसर

18 से 45 वर्ष आयु के इच्छुक दिव्यांगजन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बल्केश्वर में आवश्यक दस्तावेजों के साथ कर सकते हैं प्रतिभाग

अग्र भारत संवाददाता

आगरा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तत्वावधान में जनपद आगरा के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), बल्केश्वर में 03 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक 'दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0' का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला समन्वयक

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, आगरा ने देते हुए बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य कौशल प्रशिक्षित एवं अन्य इच्छुक दिव्यांगजन युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है। इस अभियान के माध्यम से दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा।

अभियान के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के इच्छुक दिव्यांगजन लाभार्थी 03 अगस्त से 10 अगस्त 2026 के बीच राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बल्केश्वर, आगरा में अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर प्रतिभाग कर सकते हैं। जिला समन्वयक, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने सभी पात्र एवं इच्छुक दिव्यांगजन युवाओं से अपील की है कि वे इस विशेष रोजगार अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाकर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करें।

राज्यपाल के आगमन को लेकर नगर निगम अलर्ट, संभावित रूट को लेकर दिनभर सक्रिय रहे अधिकारी

नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने अधिकारियों के साथ संभाली कमान, सफाई से लेकर सड़क और प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश

आगरा। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के रविवार को प्रस्तावित आगमन को लेकर नगर निगम प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। राज्यपाल के संभावित भ्रमण मार्ग पर व्यवस्थाएं चाक-चौबंद करने के लिए शनिवार को नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ-सफाई, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, अतिक्रमण हटाने और सौंदर्यीकरण के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए।

नगर आयुक्त ने संभावित रूट पर टाटानगर गेट, पृथ्वीनाथ फाटक, शंकरगढ़ पुलिया, रामनगर पुलिया, बोदला, कारगिल, सिकंदरा आरओबी, एनएच-19, गुरुद्वारा, आईएसबीटी, ट्रांसपोर्ट नगर, खंदारी चौराहा, खंदारी अंडरपास, विजय नगर, सुल्तानगंज, भगवान टॉकीज, दीवानी, सेंट जॉन्स, गोपाल कुंज और सूरसदन सहित अन्य प्रमुख स्थानों का जायजा लिया। जहां भी सड़क, सफाई या अन्य व्यवस्थाओं में कमी मिली, वहां संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि राज्यपाल के आगमन को देखते हुए भ्रमण मार्ग पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं रहनी चाहिए। सड़कें दुरुस्त हों, नालियों की सफाई पूरी हो, स्ट्रीट लाइटें सुचारु रूप से जलें और अतिक्रमण पूरी तरह हटाया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। नगर निगम की टीमें पूरे संभावित रूट पर विशेष सफाई अभियान चला रही हैं। डिवाइडरों की रंगाई-पुताई, झाड़ियों की कटाई, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और अवैध होर्डिंग हटाने का कार्य भी तेजी से कराया जा रहा है। इसके अलावा अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नगर आयुक्त के अलावा अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार, सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम समेत तमाम अन्य अधिकारी भी राज्य पाल के रूप का निरीक्षण करते रहे।

9 सूत्रीय मांगो को लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने दिया ज्ञापन

अग्र भारत संवाददाता

आगरा। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देश पर वर्ष 2019 के बाद लेखपाल सम्बर्ग की लंबित नौ सूत्रीय समस्याओं को लेकर प्रदेश की समस्त तहसील में अध्यक्ष राजस्व परिषद को सम्बोधित ज्ञापन तहसील दिवस के उपरांत उपजिलाधिकारी को सौंपा गया। इसी संदर्भ में आज तहसील सदर आगरा के सभागार लेखपाल संघ की मंडल स्तर की बैठक का आयोजन है । आज तहसील सदर में लेखपाल संघ की स्थानीय समस्याओं को लेकर बैठक की गयी जिसमे लेखपाल की लंबित ए सी पी, इंक्रिमेंट, सम्यसे वेतन जनगणना, आय जाति निवास,फार्मर रजिस्ट्री का मानदेय भुगतान लेखपाल से अधिकारिओं द्वारा नित नये व्यक्तिगत आदेश नियम टिप्पणी के कारण जनता की एन ओ सी हैसियत स्टाम्प कमी। पारिवारिक सदस्य प्रमाण पत्र के कारण कृषि भूमि के दाखिल ख़ारिज में अधिकारिओं, आर के प्राइवेट ऑपरेटर व प्राइवेट कर्मचारी, अधिवक्ता, मुंशी नेता की मनमानी हस्तक्षेप, अंश निर्धारण त्रुटि संशोधन आदि की समस्याओं। लेखपाल की सेवा संबंधी समस्याओं को लेकर व नियम विरुद्ध एक ही पटल पर तैनात कर्मचारी जे पटल परिवर्तन को ज्ञापन व वार्ता उपजिलाधिकारी सदर से की गयी । जिसमे तहसील अध्यक्ष सत्यदीप सिंह, तहसील मंत्री जितेंद्र चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सचिन जैन आदि द्वारा उक्त समस्याओं को पांच अगस्त तक निस्तारण का अनुरोध किया हैं अन्यथा प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देश पर अतिरिक्त क्षेत्र छोड़ने उसके बाद अधिकारिओं के व्हाट्सअप ग्रुप छोडा जायेगा।